केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया

अगले तीन वर्षों में भारत का जैविक निर्यात 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा: श्री पीयूष गोयल

जैविक खेती जल की कमी और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से निपटने के लिए एक टिकाऊ समाधान है: श्री गोयल

ट्रेसनेट 2.0, एपीडा, एनपीओपी, ऑर्गेनिक प्रमोशन और एग्रीएक्सचेंज पोर्टल का अनावरण किया गया

प्रविष्टि तिथि: 09 JAN 2025 8:39PM by PIB Delhi

भारत में जैविक खेती का कुल निर्यात मूल्य अगले तीन वर्षों में **20,000** करोड़ रुपये तक पहुंचने की क्षमता रखता है। यह बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में पूसा स्थित भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम (एनएएससी कॉम्प्लेक्स) में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के **8**वें संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में कही।

श्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक समर्पित एनपीओपी पोर्टल के साथ-साथ जैविक संवर्धन पोर्टल का भी अनावरण किया, जो जैविक हितधारकों के लिए अधिक दृश्यता और परिचालन में आसानी प्रदान करेगा।

उन्होंने ट्रेसनेट **2.0** का भी अनावरण किया, जो निर्बाध संचालन के लिए उन्नत ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है और विनियामक निरीक्षण के लिए उन्नत उपकरण हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के हितधारकों के लाभ के लिए उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव और जानकारी के साथ पुन: डिज़ाइन किए गए एपीडा पोर्टल का भी प्रदर्शन किया गया। पुन: डिज़ाइन किए गए एग्रीएक्सचेंज पोर्टल को भी लॉन्च किया गया, यह अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल डेटा विश्लेषण और कृषि निर्यात की रिपोर्ट और डेटा तैयार करने में सक्षम होगा, जिससे इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया जा सकेगा।

कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने ऑर्गेनिक ऑपरेटरों को ट्रेसनेट **2.0** पर तैयार पहले पांच पंजीकरण प्रमाणपत्र भी वितरित किए।

श्री गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में जैविक खेती के महत्व को रेखांकित किया था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने **78**वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में दुनिया भर में जैविक खेती के बढ़ते महत्व और व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा मिट्टी के पोषक तत्वों की बहाली पर इसके दूरगामी लाभों का उल्लेख किया था।

मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा पोर्टल ट्रेसनेट **2.0** के लिए आवेदन लागत को सरल बनाने और कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्री गोयल ने आगे कहा कि श्री शाह ने देश में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों के बढ़ते समुदाय का भी उल्लेख किया।

मंत्री ने कहा कि टिकाऊ कृषि पद्धति के रूप में जैविक खेती से पानी की कमी और उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से निपटने में मदद मिलेगी, जिससे देश में मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की पैदावार को नुकसान पहुँच रहा है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए श्री गोयल ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

जैविक खेती देश के लिए प्राथमिकता बन गई है और इसे दुनिया भर में खेती का एक मूल्यवान तरीका माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जैविक खेती अपनाने वाले किसानों की पैदावार और आय में वृद्धि देखी गई है। मंत्री ने कहा कि जैविक खेती भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जैविक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से सरकार को लाभ होगा।

मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए जैविक उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन पर जोर देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह मूल्य श्रृंखला रोजगार सृजन में भी मदद करेगी और देश दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल करेगा। श्री गोयल ने जैविक क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए अमूल, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र भविष्य में जैविक क्षेत्र को विकसित करने में सहायता करेंगे।

बाजार विस्तार और उत्पादों के गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसानों के लिए क्षमता निर्माण और अधिक उपज के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर शोध भी आवश्यक है। मंत्री गोयल ने कहा कि अधिक उपज से उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं के खरीद निर्णय में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के **8**वें संस्करण में किसानों सहित हितधारकों के लिए परिचालन को आसान बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख संशोधन पेश किए गए हैं। जैविक उत्पादक समूहों के लिए प्रमाणन आवश्यकताओं को सरल बनाया गया है, और इन समूहों को अब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) के स्थान पर कानूनी दर्जा दिया गया है। संशोधित छूट प्रावधानों के तहत जैविक खेती में भूमि परिवर्तन की अवधि को तीन साल तक कम करने की संभावना है, जो शर्तों और सुरक्षा उपायों पर निर्भर करती है। जैविक उत्पादक समूहों के आईसीएस को संपूर्ण जैविक उपज की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए या किसानों को सहायता करने के लिए बाजार संपर्क स्थापित करना चाहिए। सार्वजनिक डोमेन में जैविक किसानों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई गई है, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, निगरानी, सर्विलांस और डेटा एनालिटिक्स के लिए आईटी टूल्स और वेब-आधारित ट्रेसिबिलिटी सिस्टम, ट्रेसनेट के एकीकरण के साथ निरीक्षण तंत्र को मजबूत किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान अनावरण किये गये पोर्टलों का विवरण:

- एनपीओपी पोर्टल: राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के लिए समर्पित पोर्टल जैविक क्षेत्र के हितधारकों के लिए अधिक दृश्यता और संचालन में आसानी प्रदान करेगा।
- जैविक संवर्धन पोर्टल: किसान, एफपीओ और निर्यातक अपने प्रमाणित जैविक उत्पादों का प्रदर्शन कर सकते हैं, व्यापार लीड उत्पन्न कर सकते हैं और वैश्विक खरीदारों से जुड़ सकते हैं। इसमें जैविक उत्पादन

पर ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्र और जैविक व्यापार कार्यक्रमों की जानकारी भी शामिल होगी।

- ट्रेसनेट **2.0:** निर्बाध संचालन और विनियामक निरीक्षण के लिए उन्नत उपकरणों के लिए उन्नत ऑनलाइन ऑर्गेनिक ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। यह खेत से बाजार तक जैविक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और अनुपालन सुनिश्चित करेगा। कृषि के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, ट्रेसनेट हितधारकों को संचालन को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक जैविक प्रमाणन मानकों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाता है।
- एपीडा पोर्टल: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के हितधारकों के लाभ के लिए उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव और सूचना के साथ एपीडा पोर्टल को पुनः डिजाइन और नया रूप दिया गया है।
- एग्रीएक्सचेंज पोर्टल: पुनः डिज़ाइन और नया रूप दिया गया एग्रीएक्सचेंज पोर्टल अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल डेटा विश्लेषण और कृषि निर्यात की रिपोर्ट और डेटा तैयार करने में सक्षम बनाता है, जिससे यह आम जनता के लिए सुलभ हो जाता है। निर्यातक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और विक्रेताओं के साथ सहजता से जुड़ सकते हैं और साथ ही अपनी उंगलियों पर व्यापक व्यापार अंतर्दृष्टि का पता लगा सकते हैं।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) एक प्रमुख सरकारी कार्यक्रम है जो भारत की जैविक प्रमाणन प्रणाली को मजबूत करता है, टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है और किसानों और निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलता है। जैविक उत्पादों के लिए उच्च मानक निर्धारित करके, एनपीओपी वैश्विक जैविक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, साथ ही किसानों को पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके अपनाने में मदद करता है।

एनपीओपी के **8**वें संस्करण के शुभारंभ के साथ, भारत जैविक उत्पादों के अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है, जिससे जैविक मूल्य श्रृंखला में हितधारकों को सशक्त बनाया जा सकेगा। नए नियम टिकाऊ कृषि, किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, दूतावास अधिकारियों और अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे एफएओ, आईएफओएएम और एफआईबीएल के उद्योग नेताओं, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीओ) और हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और राजस्थान के **1000** से अधिक किसानों की भी भागीदारी रही।

भारतीय जैविक उद्योग की प्रतिष्ठित कम्पनियों जैसे ऑर्गेनिक इंडिया, नेचर बायो फूड्स, नेचर पर्ल्स, श्रेष्ठा, जीव अमृत, प्लांटरिच, पीडीएस स्पाइसेज, अमूल तथा सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों जैसे क्रमशः नेफेड और एनसीओएल ने भी एपीडा द्वारा लगाए गए **11** स्टालों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत शीर्ष निकाय है जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। एपीडा भारत के जैविक निर्यात क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एमजी/केसी/जीके

(रिलीज़ आईडी: 2091659) आगंतुक पटल : 579
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Bengali